

अखंड भारत संघेश

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार 05 फरवरी 2022

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरा पर्चा

इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा, यूपी में भाजपा फिर 300 के पारः गृह मंत्री

गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया। पांच बार से संसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा था। योगी के नामकन से खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। वह पहली बार है, जब शाह किसी के नामकन के लिए शामिल हुए। नामकन के बाद अमित शाह गोरक्षनाथ मठ पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इस में

योगी के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कहा, 'यूपी की जनता भाजपा के साथ है।' इस बार फिर 300 सीट जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।'

नामकन से पहले योगी ने की साधना:

नामकन से पहले सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंत्रियों में हवन-पूजन कर अर्चना की। द्रव्यधिकरण कर भगवान शिव से जीत का कामना की। इसके अलावा योगी ने अपने गृह मंहंग अवेदनात् का भी आशीर्वाद लिया। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल लिया है।

प्रस्तावकों में दिखी सोशल इंजीनियरिंग: योगी के चार प्रस्तावकों में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है। चार प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और बीच समाज के लोग हैं।

माफिया आजम-अतीक और मुख्तार जेल में ही रहेंगे: इसके पहले महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित जनसभा में अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। वह पहली बार है, जब शाह किसी के नामकन के लिए शामिल हुए। नामकन के बाद अमित शाह गोरक्षनाथ मठ पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इस में



उनको तो लगता है कोरोना के कारण साथाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा जो प्रचार करना है कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, भाजपा को फिर से 300 के पार सीटें मिलने वाली हैं।' उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार आयोजित जनसभा में होना रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है।'

बिना भेदभाव आस्था का समर्गन, सुरक्षा की गारंटी: योगी योगी आदित्यनाथ ने कहा, '2019 के चुनाव में देश और दुनिया के तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ मानते थे कि भाजपा का यूपी में क्या होगा? तब भी अपनि शाह कहते थे कि 64-65 से कम नहीं जीतेंगी। भाजपा ने बाहर 64 सीट जीतकर गढ़बंधन को फेल कर दिया था। हमसे बिना किसी भेदभाव के विकास की ओर योजनाओं को आगे बढ़ाया है।' 'हड डल छान के सकार की बदलत हो पाया है। नीतीजा कोई भी व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता।'

हिस्ट्रीशीटर को बनाएं हिस्ट्री: मोदी

उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव विकास और शांति के स्थायित्व के लिए: प्रधानमंत्री



ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डबल इंजन के बाने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को बाहर रखने के लिए है।

ये चुनाव यूपी के विकास की निरंतरता के लिए: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती-हुई देखी हैं। लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुखाना और समृद्धि के बाकर रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शॉटर को बाहर रखने के लिए है। इस बारे में यूपी विकास कार्यों को डब

संपादक की कलम से

प्रकृति की मार

कारना के संकट के बावजूद नारा पर प्रकृता का एक जाग भारतीय सालों में देखने को मिली। पिछले साल कई राज्यों में आपदा की घटनाएं देखने को मिलीं। पर्वतीय स्थलों के साथ मैदानी इलाकों में भी कुदरत का कहर जमकर बरपा। मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि देश में पिछले साल मौसम संबंधी आपदाओं में बढ़ती हुई है। साल 2021 में असामान्य मौसमी घटनाओं के कारण जो आपदाएं, आईं, उनमें दो हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए। अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो हर साल का सिलसिला है। पर इन घटनाओं को प्राकृतिक कारण मान कर भुलाया दिया जाता रहा है। मान कर चला जाता है कि ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ भी आएंगी, भूस्खलन भी होगा, तेज गर्मी पड़ेगी और पानी नहीं बरसेगा तो सूखा भी पड़ेगा। बैमौसम की बारिश दूसरी तरह के संकट खड़े करेगी। पर आज जब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और तमाम वैज्ञानिक साधन-उपकरण हमारे पास हैं, समय-समय पर मौसम संबंधी भविष्यवाणियां हमें खतरों से आगाह करती रहती हैं तो फिर हम क्यों नहीं सचेत होते? प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों, आपदाओं को जन्म देने वाली मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं विचार करते? हाल में मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट ने एक बार फिर उन कारणों को सामने रखा है, जिनकी वजह से हमें प्रकृति का कोपभाजन बनना पड़ता है। रिपोर्ट बता रही है कि गुजरा साल यानी 2021 पिछले 121 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 120 साल में जो सबसे ज्यादा ग्यारह गर्म साल रहे, वे 2007 से 2021 के बीच रहे। जाहिर है, भारतीय उपमहाद्वीप के बातावरण में गर्मी बढ़ी है। यह आने वाले समय में बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए हमें अभी से ऐसा करना होगा जिससे इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके। वरना प्राकृतिक आपदाएं और विकाराल रूप धारण कर कहर बरपाएंगी। हालांकि धरती का औसत तापमान भी बढ़ रहा है।

कुमार गोयल-
सनों वीडियो काफ्रैंस के जरिये असमानता पर आई इस रिपोर्ट के मुताबिक 142 भारतीय अरबपतियों के पास कल 719 अरब अमेरिकी डॉलर गया है कि इन अरबपतियों पर वार्षिक सम्पत्ति कर लगाने से प्रतिवर्ष 78.3 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे संख्या उसकी आधी है। एक और जहां गरीबों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, वही भारत में अब इन्हें अरबपति हो गए चिंताजनक है क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की आर्थिक सेहत में भी सधार हो।

चाहिए लेकिन गर्व भी तो तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल वेंवहां के समाज में बढ़ती

एजेंडा शिखर सम्मलन के दौरान पेश गये सरकारी संगठन ह्याउक्सफैमलू की रिपोर्ट ह्याइनड्क्वलिटी किल्स्हू के अनुसार कोरोना महामारी के दौर में अमीर जहां और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत के अरबपतियों की कुल सम्पत्ति बढ़कर दोगुने से अधिक हो गई और इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या भी 39 फीसदी बढ़कर 142 हो गई है। देश के दस सर्वाधिक अमीर लोगों के पास इतनी सम्पत्ति है, जिससे पूरे ढाई दशकों तक देश के हर बच्चे को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती है। आर्थिक

यानी 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है और देश के सबसे अमीर 98 लोगों की कुल सम्पत्ति भारत के 55.5 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल सम्पत्ति के बराबर है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महामारी के दौरान सबसे धनी 10 फीसदी लोगों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति का 45 फीसदी हिस्सा हासिल किया जबकि निचले स्तर की 50 फीसदी आवादी के हिस्से मात्र छह फीसदी राशि ही आई। रिपोर्ट में सरकार से राजस्व सृजन के प्राथमिक स्रोतों पर पुनर्विचार करने तथा कर प्रणाली के अधिक प्रगतिशील तरीकों को अपनाने का आग्रह करते हुए सुझाव दिया सरकारी स्वास्थ्य बजट में 271 फीसदी बढ़ोतारी हो सकती है। कोरोना महामारी के इस दौर में एक ओर जहां करोड़ों लोगों के काम-धंधे चौपट हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां छूट गईं, अनेक लोगों के कारोबार घाटे में चले गए, वहीं कुछ ऐसे व्यवसायी हैं, जिन्हें इस महामारी ने पहले से कई गुना ज्यादा मालामाल कर दिया है। आंकड़े देखें तो भारत में मार्च 2020 से नवम्बर 2021 के बीच देश के 84 फीसदी परिवारों की कमाई में कमी आई और 4.6 करोड़ लोग तो अत्यंत गरीबी में चले गए। इस बीच जितने लोग पूरी दुनिया में गरीबी के दलदल में फंसे, भारत में यह

हैं, जितने फ्रांस, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड को मिलाकर भी नहीं हैं। अति धनाद्य वर्ग तथा अत्यंत गरीबी में फंसे लोगों के बीच की चौड़ी होती खाई अन्य कमज़ोर वर्गों को भी प्रभावित कर रही है। आर्थिक विषमता चिंताजनक स्थिति तक बढ़ गई है और विश्व बैंक पहले ही चेतावनी दे चुका है कि दस करोड़ से ज्यादा लोग चरम गरीबी में धकेले जा सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पिछले साल भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि यदि कोरोना के कुबेरों से वसूली होती तो भुखमरी नहीं फैलती। विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता काफी सामाजिक भी पैदा होती यह तथ्य सरकार के बल एक लोगों के पास सत्तर फीसदी गुना से ज्यादा के पास देश सम्पत्ति है। हाफोर्स्डॉन द्वारा सौ से भी ज़्यादा दशक पहले भारतीय नाम वाले में अरबपति भारतीय के

ली की खेती

पर राजनीतिक विसंगतियाँ हैं। करीब दो साल पहले भूमि ने आया था कि भारत वेस्ट फ़ीसदी सर्वाधिक अमीरी ही देश की कम आय वाली आबादी की तुलना में चाहे और देश के अरबपतियाँ कुल बजट से भी ज्यादा ज विश्व आर्थिक प्रतिक्रिया अरबपतियों की सूची में दा भारतीय हैं जबकि तीन तक इस सूची में एक भूमि गई होता था। हालांकि देश की संख्या बढ़ना प्रत्येक लाए गर्व की बात होने

बहरहाल, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए। दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि देश के शीर्ष धनकुबेरों पर महज डेढ़ फीसदी सम्पत्ति कर लगाकर ही देश के कई करोड़ लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह कार्य इतना सहज नहीं है। दरअसल यह जगजाहिर है कि बहुत से राजनीतिक फैसलों पर भी अब इन धन कुबेरों का ही नियंत्रण होता असमानता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी इसके अलावा बोढ़ धर्मगुरु दलाइलामा तथा ईसई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस सहित कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां भी बढ़ती आर्थिक असमानता पर निशाना साधते हुए कह चुकी हैं कि अत्यधिक धन पिपासा समाज में एक नई प्रकार की निरंकुशता को जन्म देती है।

बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र जैसी कुछ वैश्विक संस्थाओं के अलावा कुछ देशों की सरकारें हालांकि गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं लेकिन बेहतर परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे।

र या अनुपयोगी भूमि पर बिजली की ओर अजीब अवश्य लग रही है पर सरकार इस योजना में राजस्थान लीडर प्रदेश



बनता जा रहा है। रेंगिस्तानी बंजर और अनुपयोगी भूमि का अधिकता है। यह बंजर और बिजली उत्पादन करने लगे बिजली की खरीद भी 25 साल हो जाए तो काश्तकार के लिए बात क्या हो सकती है? अनुपयोगी भूमि से बिजली तो सरकार को भी सस्ती रूप मिलेगी और काश्तकार की सुनिश्चित हो सकेगी। राजस्थान उत्पादन के लिए अनुकूल प्रदेश है। इसमें कोई दो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान यानी कुसुम योजना बंजर और खेती योग्य भूमि स्थिति से यह भूमि भी बिजली के लिए उपजाऊ हो गई है। सरकार ने कुसुम योजना के बनाए हैं और तीनों ही कंपोनेंट जुड़े होने के साथ ही उनके भी हैं। कुसुम ए कंपोनेंट तो अन्नदाता की अनुपयोगी भूमि



सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन हाँगा। उत्पादित बिजली सीधे ग्रीड में जाएगी। संबंधित ग्रीड द्वारा 25 साल तक 3 रु.14 नए पैसे प्रति यूनिट की दर से काश्तकार को भुगतान किया जाएगा। बैंकों से संवाद में यह तय हो सका कि एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया होगी जिससे डिस्काम द्वारा खरीदी गई बिजली का भुगतान सीधे

खर्च होगे। 1400 करोड़ रुपए दे दिए गए। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 13 जिलों को इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा। कटनी-पन्ना और छतरपुर जिलों में बहने वाली केन नदी 427 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना नदी में गिरती है। रायसेन के पास से निकली बेतवा नदी 576 किलोमीटर का सफर तय करती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत ढोठन (पन्ना) में डैम बनाकर केन के पानी को रोका जाएगा। यहां से 220.624 किमी की नहर बनाकर केन का पानी बुरआसागर (झांसी, यूपी) से निकली बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इसमें 2 किमी लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। बजट पर देशवासियों से बात करते हुए पर्यावरणमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा

परियोजना बुद्धिमत्ता के सूखे की स्थिति को दूर करने में मील का पथर साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुद्धिमत्ता खंड के लिए बहेद महत्वपूर्ण साबित होगी। उहोंने कहा कि अभी एमपी-यूपी के लोग काम की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व केरल तक जाते हैं। मगर केन बेतवा लिंक परियोजना की बजह से अब इन लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। इस परियोजना से किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। इससे किसानों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि आम बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को 900 करोड़ रुपए देने का परवाना मिलेगा।

इस बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं पाईं। बल्कि प्रियांका गढ़ बनवते जरूर खुश हर्दी होंगी कि उन्हें टैका में उड़ीरी दर्द है लेकिन

इस साल का जा बजट पर एकता गया है, उसे भाजपा के नेता अगले 25 साल और 100 साल तक के भारत को मजबूत बनानेवाला बजट बता रहे हैं और विपक्षी नेता इसे बिल्कुल बेकार और निराशाजनक घोषित कर रहे हैं। वैसे जब इस बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थीं तो उनके भाषण को सुननेवाले लोगों को, खासतौर से सामान्य लोगों को लग रहा था कि इस बजट में उनके लिए कुछ नहीं है। सरकार ने न तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ न कुछ चीजों को सस्ता करने की घोषणा की है, न आयकर को घटाकर मध्यम वर्ग को कोई राहत दी है और न ही

पड़ा। कुल सरकार वह बजट निर्मुण निराकार-सा लगता रहा लेकिन जब इसके सारे आंकड़े अलग से विस्तारपूर्वक सामने आए और टीवी चैनलों पर तरह-तरह की बहसें सुनीं तो लगा कि इस बजट में बुनियादी सुधार के कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा जनता को सरल भाषा में अच्छी तरह समझाना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बजट में कहीं भी ऐसी झलक नहीं है कि इसका पांच राज्यों के चुनाव से कुछ संबंध है। हर व्यक्ति यह सोच रहा था कि इन पांचों राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकार इस बजट का इस्तेमाल जरूर करेगी।

टक्के में कटाओ ७२ लाख सरकार ने जो सपने इस बजट में दिखाए हैं, यदि वह इन्हें ठोस रूप दे सकी तो लोक कल्याण काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जैसे वह 60 लाख नए रोजगार देगी, 400 नई रेल चलाएगी, सारे गंगातटीय प्रदेशों में जैविक खेती को बढ़ावा देगी, 80 लाख मकान गरीबों को देगी, 200 नए टीवी चैनलों द्वारा मातृभाषा वे जरिए शिक्षा का प्रसार करेगी लगभग 4 करोड़ घरों में नलों द्वारा शुद्ध जल पहुंचाएगी, पांच नदियों को जोड़ेगी, 25000 किमी की न सड़कें बनाएगी, लघु-उद्योगों वे प्रोत्साहन में सवा दो लाख करोड़ रु. लगाएगी। इस तरह की घोषणाएँ सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन

धजट ना दिखा आत्मनिर्भर नाटत का झालफ

-सुरेश हिन्दुस्तानी-
कौरोना काल के दौरान केन्द्र सरकार का दूसरी बार प्रस्तुत किया गया बजट कई मायनों में मील का पथर प्रमाणित होने वाला दिखाई दे रहा है। वहीं यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जाने वाले मार्ग को और सुगम बनाने वाला भी है। भारत में आत्मनिर्भरता के द्वारा कृषि और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से ही खोले जा सकते हैं इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि उन्नयन और युवाओं को रोजगार देने के लिए पिटारा खोला। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश की भावी तस्वीर का खाका खींचते हुए बेरोजगारी समाप्त करने की पहल की है, जिसके अंतर्गत युवा वर्ग को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं, मेक इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। हालांकि ये नौकरियां नियमित नहीं होनी चाहीं हैं।

वाला बने। इसके लिए सरकार ने पहले ही लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। जिसका उपयोग करके युवाओं ने अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाकर सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने ठोस प्रावधान किया है। लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से जहां स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते। इससे बड़ा लाभ यह भी है कि उद्यम जगत की प्रतिभाओं को अपने शहर या गांव में ही कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस कदम को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बात सही है कि वर्तमान में जिज्ञापनों के मोहजाल में फंसाकर बहुराष्ट्रीय

सकारात्मक प्रयासों के चलते इस धारणा में व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। भविष्य में भी सरकार ने अपने बजट में इसे प्रभावी आकार में स्थापित करने की मंशा दिखाई है। इसके अलावा वित्तमंत्री ने आर्थिक जगत में आई तकनीकी क्रांति के साथ कदम मिलाते हुए कहा कि इसमें सफलता के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। यह विदेशी क्रिप्टो करंसी के एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम माना जा रहा है। भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वह अपने देश की क्रिप्टो करंसी बनाएंगी। वर्तमान में कदम-कदम पर डिजिटल अवधारणा को प्रमुखता दी जा रही है। आज का बाजार भी डिजिटल रूप में विकसित होता जा रहा है। सरकार की भी यही योजना है कि देश का पैसा देश में ही रहे। इसे भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी खरीद पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद 163 लाख किसानों

